सरकारों से, जो कार्यान्वयन प्राधिकारी हैं, इन प्रावधान के कठोर प्रवर्तन के लिए समय-समय पर अनुरोध किया गया है ।

(ख) और (ग) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अंतर्गत आवास, चिकित्सा, मनोरंजन और शैक्षणिक सुविधाओं दी गयी हैं । बीड़ी कर्मकारों के लिए चलायी जा रही कल्याण योजनाओं की एक सूची विवरण के रूप में दी गयी है ।

विवरण

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अंतर्गत चलाई जा रही कल्याण योजनायें

स्वास्थ्य

1. तपेदिक अस्पतालों में पलंगों का आरक्षण ।
2. कैंसर से पीड़ित कर्मकारों की वास्तविक उपचार खर्च की प्रतिपूर्ति ।
3. मानसिक रोगों से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के उपचार के लिए सुविधा देने की योजना ।
4. बीड़ी कर्मकारों (घर खाता कर्मकारों सहित) को मुफ्त चश्मा देने की योजना ।
5. हृदयरोगों की चिकित्सा की योजना ।
6. बीड़ी कर्मकारों के लिए कुष्ठ-राहत योजना ।
7. तपेदिक से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों का घर पर उपचार ।
8. गुर्दाप्रतिरोपण आदि के लिए बीड़ी कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में खर्च की प्रतिपूर्ति देने की योजना ।
9. महिला बीड़ी कर्मकार के लिए प्रसूति प्रसुविधा योजना ।
10. बीड़ी कर्मकारों की नसबंदी के लिए आर्थिक प्रतिपूर्ति की योजन
11. उन बीड़ी कर्मचारी के लिए सामूहिक बीमा योजना जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सदस्य नहीं हैं–01 अप्रेल, 1992 से आरम्भ की गयी है ।

शिक्षा

1. बीड़ी कर्मकारों के बच्चों को छात्रवृत्ति देना ।
2. स्कूल जा रहे बच्चों को ड्रेस का सैट देने के लिए वित्तीय सहायता ।

आवास

1. अपना मकान स्वयं बनाओ योजना ।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना ।
3. बीड़ी कर्मकारों के लिए सामूहिक आवास योजना ।
4. वर्कशेडों और गोदामों के निर्माण के लिए बीड़ी कर्मकारों के सहकारिता सोसायटी को वित्तीय सहायता देना ।

मनोरंजन

1. दृष्य श्रव्य सैटों/सिनेमा वैन/फिल्म प्रदर्शन की योजना ।
2. खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना ।
3. अवकाश गृहों के प्रावधान की योजना ।

Child Labour engaged in Hazardous work

2075. SHRI RAMSINH RATHWA:

SHRI SURESH PACHOURI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Goverament have done any survey regarding the existing child labour in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) how many children are employed in hazardous industries such as Beedi factories, bangles industry, carpet industry, chemical factories etc.;

(d) whether Government have also made a survey to find out the child labour in Madhya Pradesh;

(e) if so, the details thereof; and

(f) what action Government propose to take to improve the lot of child labour in the country?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SING GHATOWAR): (a) to (c) The latest Census figures available are with reference to the year 1981. According to this, the number of Child labour in the age group of 0-14 years in the country was 13.6 million. As per the 43rd round of survey conducted by the National Sample Survey in 1987-88, the number of child labour was 17 million. No authentic data on the number of child labour engaged in different industries are available.

(d) and (e) The number of child labour in Madhya Pradesh as per 1981 census was 1,698,597.

(f) There are a number of legislations which prohibit the employment of children below 14 years in certain occupations/processes and regulate their conditions of work in other areas with a view to protect them from exploitation at work and also to improve their working conditions. The National Policy on Child Labour, 1987, *inter alia*, envisages project based plan of action in areas of concentration of child labour and focussing on general development programmes for the benefit of child labour. Financial assistance to voluntary organisations is also provided to take action oriented project.

2076. [*Transferred to the 11th May, 1992.*]

Family pension to workers

2077. SHRI S. MADHAVAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Central Board of Trustees has formulated any scheme to utilise the portion of the Employers' share of workers' Provident Fund for family pension to the workers;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether Government have consulted the workers on this matter, and if so, the reaction of the workers thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SING GHATOWAR): (a) to (c) The Central Board of Trustees, Employees Provident Fund is a tripartite body consisting of representatives from employees, employers and Government. The Board has unanimously recommended introduction of a suitable Pension Scheme for all provident fund subscribers utilising the employers' share of PF contribution alongwith the existing family pension fund. The Scheme provides for payment of monthly pension in the case of retirement, superannuation, death etc.

खाली पड़े आरक्षित पद

2078. **श्री अजीत जोगी :**

कुमारी आलिया :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम मंत्रालय में इस वर्ष के प्रारंभ में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अधिकारियों और अन्य श्रेणियों के कितने कितने पद खाली पड़े थे ;